P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण युवाओं की सामाजिक चेतना एवं सशक्तीकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी,
शिक्षा संकाय,
आर0बी0एस0 कालेज,
आगरा

सारांश

भारत प्रगतिशील युवा आबादी वाला देश है। यहां जनसंख्या का 68 प्रतिशत हिस्सा गांवों में बसता है और इसमें भी लगभग 45 प्रतिशत युवा है। 2040 तक भारत विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश बन कर उभरेगा। ऐसी स्थिति में अपने शक्ति को संसाधन स्वरूप में बदलने के लिये, बहुत ही व्यापक प्रयास करने होंगे। और इसके लिये हमें अपने ग्रामीण युवाओं को उच्चशिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं पुनर्गठन संस्थाओं के करीब लाना होगा और उनके सशक्तीकरण में संरचनात्मक तरीके से वृद्धि करनी होगी, इन्हें देश के विकास में योगदान करने के लिये, स्टार्टअप, स्टैण्डअप इण्डिया कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों से जोड़ कर स्वावलम्बी बनाना होगा। युवा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। वह देश का भाग्य बदल सकते हैं और अपना भाग्य बदलने के लिये प्रयत्नशील हर राष्ट्र के पास उद्भुद संसाधनों के उपयोग करने के रास्ते और उपाय होने चाहिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार कहा था ''हम हमेशा अपने युवाओं का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य के लिये अपने युवाओं को तैयार जरूर कर सकते हैं।

मुख्य शब्द : युवा, सामाजिक चेतना, सशक्तीकरण।

प्रस्तावना

औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाए समाज में शिक्षा को तीन परिवर्तनकारी दायित्व निभाने होते हैं। क्रमशः मस्तिष्क और ज्ञान प्रणाली को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाना, संसाधनों का विकास और कमजोर एवं पिछड़े वंचित वर्गों के शिक्षा की कमी को दूर करके निर्माणात्मक प्रक्रिया में समावेश करना। भारत के सम्बन्ध में इसे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया या इसका संवर्धन कहा जा सकता है। विदेशी शासन से आजादी के पश्चात हमारे शिक्षा के ढांचे की समीक्षा इस मायने में और भी उपयोगी बन जाती है जब हमारी चुनौतियों की कतार बहुत लम्बी हो। स्वातंत्रोत्तर परिदृश्य में हमने 1947 में अपनी शिक्षा यात्रा की शुरूआत 12 प्रतिशत साक्षरता और 20 से भी कम विश्वविद्यालयों के साथ की थी भारत वर्ष 1951–52 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.6 प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय कर रहा था, केवल 0.7 प्रतिशत लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, और महिलाओं में भी साक्षरता की दर केवल 2 प्रतिशत थी, आज वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती हुयी आबादी, के लिये बहुत सारे शैक्षणिक संसाधनों को समग्र करके उनको एक सकारात्मक दिशा में लगाना होगा, और रोजगार प्रदाताओं का देश बनना होगा। कोई भी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय नीति के ढांचे और उसके लिए समग्र प्रावधानों के अंतर्गत समाज के दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम शिक्षकों की प्रतिबद्धता अभिभावकों की सहभागिता और छात्रों के रवैये से आकार ग्रहण करती है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है जिसमें 70 प्रतिशत भारतीय आबादी गांवों में निवास करती है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था भी कृषिगत सहयोग से अछूती नहीं है। भारत के विकास, सुख, समृद्धि का भी यह आधारभूत क्षेत्र है जो आज अपनी अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है। स्वतन्त्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास एक चुनौती रही है एवं यहां पर निवास करने वाली आबादी को योजनाबद्ध तरीके से आज भी विकास की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जा सका है। हमारी ग्रामीण समाज आज भी बेरोजगारी, आर्थिक तंगी एवं कृषि पर ही ज्यादा निर्भर है और यह महसूस किया गया है कि इन अंधकार मय परिस्थितियों का कहीं न कहीं जिम्मेदार चिरस्थायी कार्यनीति की कमी रही है। गरीबी, अज्ञानता, रोगों तथा अवसरों का असमानता को दूर करना और देशवासियों को बेहतर तथा उच्च

जीवन स्तर प्रदान करना तभी संभव हो सकता है जब हम ग्रामीण युवाओं का शैक्षिक समावेशन करके उनके अन्दर सामाजिक चेतना उत्पन्न करें और उन्हें रोजगार के सार्थक अवसर प्रदान करें 2040 तक हम सबसे युवा आबादी वाले देश होंगे, जिसमें आज भी गांवों में इस आबादी का एक बड़ा भाग निवास करता हैं। जिसे मानव संसाधन के रूप में बदलना होगा, मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन है। और एक बड़ी सम्पत्ति माना जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका संक्षेप में निम्नवत् हाती है– संसाधनों के कुशल उपयोग, उत्पादन एवं खपत, कौशल एवं बुद्धि की आपूर्ति श्रम शक्ति की आपूर्ति, सभ्य समाज के निर्माण में, पूँजी निर्माण, राष्ट्रीय रक्षा अतः इन सभी क्षेत्रों में कुशल एवं प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली युवाओं एवं कामगारों की आवश्यकता है, जिसे हम बेहतर प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा एवं योजनाबद्ध तरीके से सम्बन्धित कर अर्थव्यवस्था में समायोजित किया जा सकता है। अतः शोध का महत्व तब और भी बढ़ जाता है, जब हमारा ग्रामीण समाज विकास में योगदान करने के लिये तत्पर खड़ा है परन्तु उसके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इन्हीं बुनियादी सुविधाओं का विश्लेषण शोधार्थी द्वारा अपने शोध में किया गया है। और यह बताने का प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का विश्वविद्यालयों, एवम् समाज में सुलभता कहाँ तक है और अभी कौन–कौन से प्रयास करने की आवश्यकता है।

साहित्यावलोकन

माइलम एण्ड हरटड़ों (2001) ने सामाजिक चेतना के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया और पाया कि समाज में आतंकवाद, बेराजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे कारक इसको परिलक्षित करते है। व्यक्ति किसी समस्या को जिस नजरिये से देखता है उसी प्रकार की अभिवृत्ति विकसित होती है।

डब्ल्यू0 ई0बी0 दुहिस (2003) ने अपने शोध अध्ययन में अफ्रीकी मूल के लोगों की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डाला और बताया कि आज भी 21वीं शदी में भी अफ्रीकी मूल के गोरे व काले का भेद विद्यमान है और अफ्रीकी मूल के लोगों में आज भी रंगभेद विद्यमान है।

सिंह, राजेन्द्र (2011), ने अपने शोध उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक, परिपक्वता, आत्मविश्वास, एवं कुंठा का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति से सम्बन्धित एक अध्ययन में पाया कि जिस छात्रों की सामाजिक परिपक्वता उच्च है। उनकी शैक्षिक निष्पत्ति भी उच्च स्तर की है।

प्यारी, आनन्द (2013) ने अपने शोध महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, जीवन संतुष्टि एवं समायोजन पर युवा मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन में पाया कि मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के लिये बहुत ही आवश्यक है।

लेडफोर्ड, मेरीडिन किंग ल्यूकस, ब्राउन (2013) में अपने लेख पत्र युथ इम्पावरमेण्ट द थ्योरी एण्ड इट्स इम्पलीमेन्टेशन में युवाओं की समस्याओं एवं इसके समाधान पर विस्तृत व्याख्या दी है।

रोजर, ए0 हर्ट (2013) ने चिल्ड्रेन पार्टिसिपेशन, द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ इनवाल्विंग सिटीजन्स इन कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट एण्ड इनवायरमेन्टल केयर, में सहभागिता पूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से युवा द्वारा सामाजिक विकास किया जा सकता है।

यूरोपियन कमीशन (2015) के लेख पत्र, इम्पावरिंग यंग प्यूपल इन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी में विस्तारपूर्वक यह बताया है कि युवाओं को किस प्रकार समुदाय से और अधिक जोड़ा जाये एवं उनमें तारतम्यता कैसे स्थापित की जाये।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शोध अध्ययन में युवाओं में सामाजिक चेतना, विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं आयु वर्ग के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. नेहरू युवा केन्द्रों, सरकारी योजनाओं एवं उच्च शिक्षा के संयोजक घटकों का युवाओं के सशक्तीकरण में योगदान का अध्ययन।
3. बढ़ती बेरोजगारी, एवं घटते रोजगार के कारणों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में वर्णानात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014–15 के आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित रहेगा।
2. प्रस्तुत शोध बेरोजगारी दर, रोजगार उन्नयन के सरकारी प्रयासों के विश्लेषणात्मक अध्ययन तक सीमित रहेगा।
3. नेहरू युवा केन्द्रों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े प्रमुख नियामक संस्थानों तक सीमित रहेगा।

शोध की जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध की प्रकृति सर्वेक्षणात्मक है तथा उसका सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर है। इसमें ग्रामीण युवाओं, उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस शोध में न्यादर्श चयन का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 18 से 30 आयु वर्ग की समग्र जनसंख्या ही न्यादर्श है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर प्रमाणिक सूचनायें प्राप्त करने के लिये सरकारी अभिलेखों का उपयोग किया गया है, एवं शिक्षा सर्वेक्षण 2014–15 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत, रिपोर्टों का अध्ययन किया गया।

युवाओं में सामाजिक चेतना

किसी भी राष्ट्र के युवा उसकी संपन्नता के रखवाले होते हैं। विकसित दुनिया के अधिकतर देश बूढ़ी होती जनसंख्या वाले राष्ट्र बनते जा रहे लेकिन भारत 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश बनने जा रहा है। भारत की आबादी में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली आबादी सबसे गतिशील एवं जीवंत स्थिति वाली है। भारत में आज भी 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का निवास है। और उसमें भी 40 प्रतिशत से ज्यादा युवा रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को अपने तीव्र विकास दर को बरकरार रखना है तो इन युवाओं तक वो हर सुविधायें पहुँचानी

होगी जिसके यह हकदार हैं। इन युवाओं में राष्ट्र निर्माण की अद्भुत क्षमता है, इसलिए उनकी रचनात्मकता उत्साह ऊर्जा एवं बहुमुखी प्रतिभा को उच्च अध्ययन से त्वरित जोड़ कर क्रांतिकारी उत्पादन करना होगा, जिसमें, हमें सभी घटकों में एक साथ सुधार लाना होगा अन्यथा हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तिहरे न्याय के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की आंतरिक आवश्यकता और आधुनिक विश्व प्रणाली में अन्य प्रतियोगियों से प्राप्त होने वाली बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमारी शैक्षिक संरचना के सभी तीनों स्तरों प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों में सृजनात्मकता का संवर्धन करना होगा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग से अध्ययन के नए तरीकों के गहन उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण युवाओं में सामाजिक चेतना पैदा करनी होगी, हर एक गांव में एक नाटकशाला, पाठशाला, पुस्तकालय एवं Computer Lab, खेलकूद के मैदान विकसित करना होगा, जिससे वह गांव समाज के साथ जुड़ सकें और गांधी जी की कही हुई पंक्ति ''भारत का भविष्य गांवों में बसता है'' को चरितार्थ कर सके और हर स्तर से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये तत्पर हो सकें।

युवा सशक्तीकरण

माइकल ग्रीन ''यूथ इज एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में कहते हैं, ''युवाओं के सकारात्मक विकास की लगातार विस्तार लेती तथा प्रभावशाली गति को देखते हुये उनकी ताकतों तथा रूचियों पर हमारा ध्यान होना चाहिए उन्हें कमियां दूर करने का साधन नहीं माना जाना चाहिए, और समस्याओं पर केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समस्याओं का समाधानकर्ता का दृष्टिकोण होना चाहिये। युवा सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हे जिसमें बच्चों और युवाओं को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें युवा स्वयं की स्थिति को देख समझकर अपने व्यवहारिक मूल्यों के माध्यम से अपनी सामाजिक चेतना का कायाकल्प करने का प्रयास करते है। युवा सशक्तीकरण का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

युवा सशक्तीकरण युवा विकास से भिन्न है। क्योंकि विकास एक पर केंद्रित होता है। वरन् सशक्तीकरण समुदाय से संबंधित है। जिसके माध्यम से युवा और सम्पूर्ण समुदाय के बीच स्वायत्त और आत्मनिर्णय को बढ़ाने में मदद देते है। जिससे यह समूह अपने अधिकार क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्ण और अपने तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। युवा सशक्तीकरण के तीन आधार होते है। व्यक्तिगत सशक्तीकरण, संगठनात्मक सशक्तीकरण,सामुदायिक सशक्तीकरण। व्यक्तिगत आधारों को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा एवं सामाजिक न्यास परिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। परन्तु हमें उससे पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना होगा जिसमें भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर, श्रमिकों की भागीदारी दर, शिक्षा के स्तर पर आयु वर्ग पर आधारित बेरोजगारी दर आदि।

सारणी–1

विभिन्न आयु वर्गों में बेरोजगारी दर (U.P.S.) 2015, 2016

	15–17 वर्ष			18–29 वर्ष			30 + वर्ष से अधिक		
	पु0	म0	व्य.	पु0	म0	व्य.	पु0	म0	व्य.
ग्रामीण	18.4	22.8	19.5	11.2	17.9	12.7	0.9	3.7	1.6
शहरी	22.1	21.4	22.4	11.5	27.9	15.1	0.7	5.3	1.5
कुल	18.8	22.7	19.8	11.3	20.0	13.2	0.9	4.0	1.6

यूपीएस युजुअल प्रिंसिपल स्टेट्स, पु0–पुरूष, म0–महिला, व्य–व्यक्ति स्रोत श्रम ब्यूरो युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट 2015–2016

बेरोजगारी दर उन लोगों का अनुपात होता है। जो काम के लिए उपलब्ध हो परन्तु उनको रोजगार की सुलभता न हो सकी हो, 2015–16 में 18–29 आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 13.2 प्रतिशत तथा 30 से अधिक आयु वाले श्रमिकों की बेरोजगारी दर 1.6 प्रतिशत थी, शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षा के स्तर बढ़ने के साथ–साथ युवाओं में बरोजगारी भी बढ़ रही।

सारणी–2

शिक्षा के स्तर और आयु वर्ग पर आधारित बेरोजगारी दर (U.P.S.)

वर्ष	18–24 वर्ष			30 + वर्ष		
	पु0	म0	व्य.	पु0	म0	व्य.
शिक्षा	4.0	6.2	4.9	0.6	3.0	2.2
अधूरी प्राथमिक शिक्षा	4.8	5.8	5.1	0.6	1.9	1.6
प्राथमिक शिक्षा	5.5	8.0	6.2	0.6	2.3	1.0
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर मा0	9.2	17.1	10.4	0.7	4.8	1.6
स्नातक से पूर्व सर्टिफिकेट कोर्स	21.3	31.3	23.5	0.6	11.2	2.4
स्नातक स्तर पर डिप्लोमा	20.9	33.1	23.0	1.0	7.6	1.4
स्नातक और अधिक	29.7	47.7	34.8	2.3	13.5	6.2
कुल	11.3	20.0	13.2	0.9	4.0	1.6

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

रोजगार पाने योग्य बनाने के लिए सरकारी पहल

प्रत्येक वर्ष श्रम बाजार में सृजित होने वाली नौकरियां युवाओं की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिये कई रोजगार सृजन योजनाएं प्रारम्भ की गई है। जैसे– प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मेक इन इण्डिया और स्किल इण्डिया, स्टार्ट अप प्रोग्राम, ग्राम उद्यमिता प्रोग्राम जैसी सरकारी पहलों से ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी युवाओं को समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014–15

Response of Universities during 2015-16

Type of university	Number of Universities	Number of Response*
Central Open University	1	1
Central University	43	41
Deemed University- Government	32	32
Institution Under State Legislature Act	5	4
Institution of National Importance	75	74
Deemed University- Private	79	79
State Private University	197	182
State Open University	13	13
State Public University	329	326
State Private Open University	1	1
Deemed University- Government Aided	11	11
Others	13	10
Grand Total	799	774

छठवीं अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014–15 के अनुसार वर्ष 2010–11 के 19.4 प्रतिशत की तुलना में 2014–15 में सकल नामांकन अनुपात 23.6 प्रतिशत रहा है। जिसे वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

	University	Colleges	Standalone
Listed for AISHE 2015-16	799	39071	11923
Response in AISHE 2015-16	754 (94.4%)	33903 (86.8%)	7154 (60%)
Total number of Institutions after pooling data from AISHE 2013-14 and AISHE 2014-15	774 (96.9%)	35667 (91.3%)	7915 (66.4%)

यह सर्वेक्षण देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में किये गये और संस्थानों का वर्गीकरण करते हुये विश्वविद्यालय स्तर, कालेज स्तर और एकल संस्थान के स्तर पर विभक्त किए गए हैं। इस रिपोर्ट में 799 विश्वविद्यालय, 39071 कालेजो और 11923 एकल संस्थानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचनाएं भेजने का प्रस्ताव किया गया था जिसमें 754 (94.4 प्रतिशत) विश्वविद्यालयों 33903 (86.8 प्रतिशत) कालेजों तथा 6837 एकल संचालित संस्थानों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किये और इन आंकड़ो से यह पता चला कि भारत में सर्वाधिक कालेजो की संख्या वाले 7 राज्य क्रमशः–उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है।

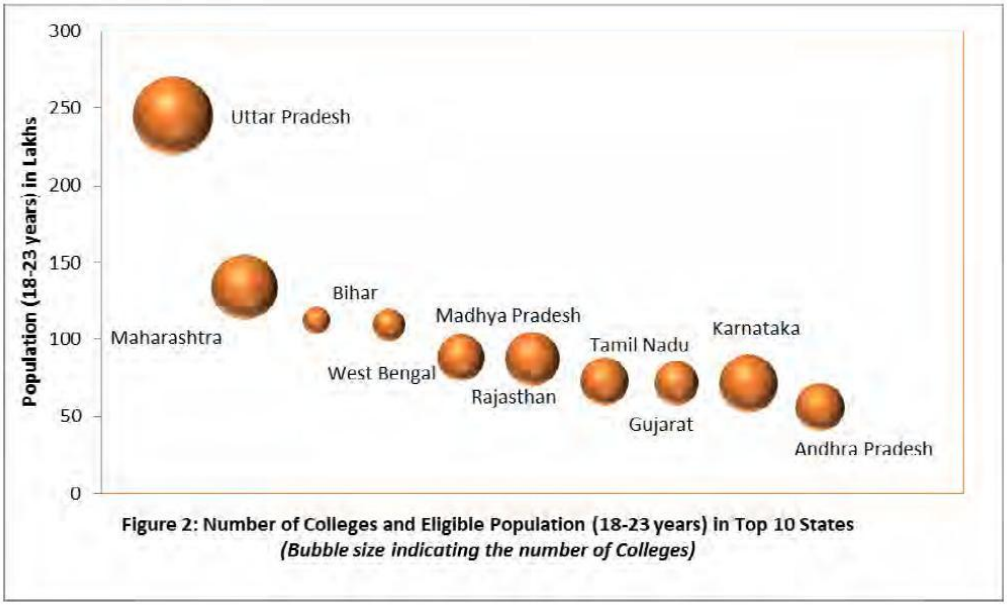

Figure 2: Number of Colleges and Eligible Population (18-23 years) in Top 10 States
(Bubble size indicating the number of Colleges)

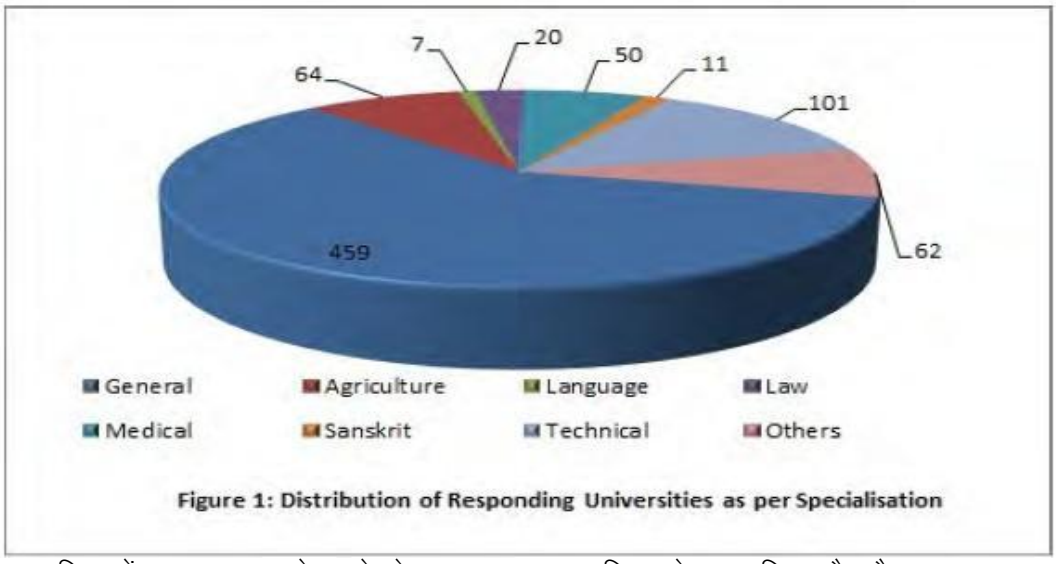

Figure 1: Distribution of Responding Universities as per Specialisation

उच्च शिक्षा में दूरस्थ माध्यम से इनरोलमेन्ट 11.7 प्रतिशत रहा जिसमें 46 प्रतिशत महिलाएं है। भारत में 112812 छात्र पी0एच0डी में नामांकित है जो कि कुल नामांकन के 0.39 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के छात्रों का कुल नामांकन 13.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति छात्र कुल नामांकन 4.8 प्रतिशत है। 32.9 प्रतिशत छात्रों को अन्य पिछड़ी वर्ग में शामिल है। जिनमें 4.4 प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यक और 1.9 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

देश उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कुल संख्या 1418389 है। जिनमें 61 प्रतिशत पुरुष शिक्षक हैं और 39 प्रतिशत महिला शिक्षक है और आज भी छात्र शिक्षक अनुपात विश्वविद्यालयों और कालेजो में 24 का है।

रोजगार सृजन में उच्च शिक्षा की उपादेयता

क्षमता एवं गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से रोजगार सृजन में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमें U.G.C., NCTE, NUPA, HEFA, MHRD जैसे संगठनों ने क्रमिक योगदान किया है और व्यापक स्तर पर सुधार प्रस्तुत किये हैं। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है।

1. पाठ्यक्रम में उद्योग प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
2. उद्योग आधारित प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की दृष्टि से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार लाना।
3. योग्य इंस्ट्रक्टर्स का व्यापक दायरा विकसित करना, एवं पाठ्यक्रमों में शोध करने, एवं व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षाशास्त्र को समाहित करना।
4. भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
5. शैक्षिक पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना।
6. उच्चता शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना होगा।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण सुधार हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ज्ञान, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, पंडित

मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जैसे कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

युवा सशक्तीकरण एवं सामाजिक चेतना में नेहरू युवा केन्द्र का योगदान

विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनो में से एक एन. वाइ.के.एस का उद्देश्य युवाओं को व्यक्तिगत और नेतृत्व गुणों का विकास और उन्हें राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में संलग्न रखना है। जिसके लिये राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रमों का योगदान महत्वपूर्ण है।

सारणी–3

एन.वाई.के.एस. के विविध कार्यक्रम (2014–15, 2015–16)

आयोजित कार्यक्रम के नाम	उद्देश्य	कार्यक्रम	प्रतिभागी
युवा नेतृत्व और समुदाय विकास प्रशिक्षण	युवा वर्ग में क्षमता व राष्ट्रीय निर्माण करना	4693	205298
थीम बेस्ड जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि सामाजिक मुद्दों पर जागृति लाना	11526	895895
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक कौशल का विकास करना	13214	276552
खेलों का संवर्धन	खेल सामग्री और प्रबंधन	6875	750215
लोक कला और संस्कृति संवर्धन	युवा कृतियों को बढ़ावा देना	1114	215694
राष्ट्रीय ओर अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिनों का अनुपालन/प्रेक्षण	राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना	24527	2696017
युवा क्लब विकास कार्यक्रम	युवा क्लबों को मजबूत करना	4098	308474
यूथ कन्वेंशन और युवा कृति	ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण	1165	268782

सारणी–4

एन.वाई.के.एस. के विविध पहलें (2014–15, 2015–16)

आयोजित कार्यक्रम	उद्देश्य	कार्यक्रम	प्रतिभागी
राष्ट्रीय एकीकृत कैंप	सांस्कृतिक विरासत समझ विकसित करना	122	23591
युवा नेतृत्व व व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	ग्रामीण उत्तरदायित्व विकास करना	23	690
किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण	किशोरों के सशक्तीकरण करना	497	16057
जोखिम कैंप	युवाओं को साहसी बनाना	286	7009

भारत में युवाओं को बहुस्तरीय चुनौतियों से लड़ने के लिये नीति आयोग ने 23 अप्रैल 2017 को प्रकाशित ड्राफ्ट थ्री ईयर विजन, स्ट्रेटजी एण्ड एक्सन एजेंडा 2017–18 टू 2019–20 में युवाओं के लिये ज्यादा सशक्तीकरण और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिये, उत्पादकता और कार्यबल को बढ़ाने के लिये ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण युवाओं में शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना लक्ष्य रखा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

गांधी जी के अनुसार ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केन्द्र होता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक संकल्पना है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में पिछड़ गये है। ग्रामीण विकास के लिये शिक्षा और कौशल विकास, जन स्वास्थ्य, उत्पादकता मूलक संसाधनों का विकास, निर्धनता, आधारभूत संरचना (बिजली, पानी, सड़क) जैसे तत्वों को नवीन तकनीकी के माध्यम से सर्वसुलभ बनाने एवं गांवों में उद्यमिता को नया माहौल देना होगा और यह सब तभी सम्भव है। जब हम सामाजिक न्याय की अवधारणा (प्रकृति न्याय एवं संसाधनों पर समान अधिकार) को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अवसरों की समानता को धरातलीय स्तर पर उतार सकेंगे। युवा बल को युवा शक्ति में रूपांतरित करना होगा और उन्हें अपने स्वभाव को पहचानने का प्रशिक्षण देना होगा, स्वभाव के अनुरूप कार्य का चयन करने से पूरी क्षमता व संभावना का विकास हो सकता है। जिसमें उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना होगा यह प्रयास ग्रामीण युवाओं का कृषि से हुए मोहभंग को फिर उन्हें कृषि कार्यों की ओर खींच लाएगा, इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकता है। यह ध्यातव्य है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक रोजगार सृजन किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार को इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और एक ऐसे तन्त्र विकसित करने की जरूरत है, जिसमें युवाओं की उम्र, योग्यता, रूचि प्राथमिकता, समस्या आदि पर एक बृहद डाटावेस तैयार किया जाये और इन्हीं प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ही युवाओं के लिए एक समग्र नीति बनायी जाए। युवाओं के हर समस्याओं एवं संबंधित पहलुओं के समाधान एक ही नोडल सेन्टर से संचालित किये जाये, प्रत्येक संगठन/संस्था/विभाग में नागरिक घोषणापत्र को पारदर्शी रूप से लागू किया जाये और सभी योजनाओं/कार्यों/गतिविधियो से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये, तथा इनका मूल्यांकन सतत् होना चाहिये। जिससे वास्तविक स्थिति का पता चले और नवीन प्रयास जारी रहे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *झूनझूनवाला, अशोक, (जनवरी 2016), मेक– इन– इण्डिया मिशन के आइने में शिक्षा अनुसंधान एवं विकास, योजना : नई दिल्ली, वर्ष 60, अंक 1, पेज 37*

2. *सुनीता, (जून 2017), भारतीय युवाओं की वैश्विक मौजूदगी, योजना, अंक, 06, पेज 27*
3. *सान्याल, सौरभ, (2017) रोजगार प्रदाताओं की वैश्विक मौजूदगी, योजना, नई दिल्ली, अंक 06, पेज 21*
4. *अलख, एन शर्मा (जून 2017), भारत में युवाओं के लिए रोजगार, योजना : नई दिल्ली, अंक 06, पेज 13*
5. *प्रसाद, श्याम सुन्दर (जून 2017), सशक्त युवा के लिए सम्मिलित नीतियां जरूरी, योजना : नई दिल्ली, अंक 06, पेज 43*
6. *कुमार, आनंद (अक्टूबर 2013), शिक्षा परिदृश्य में गुणवत्ता क्रांति की आवश्यकता, योजना : नई दिल्ली, पेज 56–57*
7. *दूबे0, ए0के0 (जून 2017), भारतीय युवा : उभरती चुनौती, योजना; नई दिल्ली, अंक 06, पेज 9, 12*
8. *http://wwwmainarityaffairs.gov.in/sites/default/fles /hindi_Booklet pdf*
9. *http://nili.gov.in/writereaddata/files/coop/ActionPla n.pdf/p.2, 151-52.*
10. *www.yas.nic.in*
11. *Economic Survey Report 2016-2017*
12. *www.labour bureau report*
13. *mhrd.gov.in>highereducation*
14. *mhrd.gov.in>scheme*
15. *http://ndl.handle.net/10603/9290*
16. *http://hdl.handle.net/10603/18811*
17. *http://hdl.handle.net/10603/26781*
18. *http://hdl.handle.net/10603/134273*
19. *http://hdl.handle.net/10603/186413*